भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 5699
दिनांक 04.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत का वैश्विक प्रभाव

5699. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार संयुक्त राष्ट्र, जी-20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के वैश्विक प्रभाव का विस्तार करने के लिए किस प्रकार काम कर रही है;
(ख) सरकार द्वारा वैश्विक दक्षिण(ग्लोबल साउथ) के साथ भारत की संलग्नता को सघन करने और पारस्परिक संवृद्घि तथा विकास साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है; और
(ग) सरकार का वैश्विक सहयोगियों के साथ सुरक्षा जोखिमों के विरुद्घ सक्रिय रक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुफिया-साझाकरण समझौतों को किस प्रकार बढ़ाने का विचार है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री पबित्र मार्गेरिटा]

(क) संयुक्त राष्ट्र, जी-20, ब्रिक्स और क्वाड जैसी विभिन्न बहुपक्षीय और अनेकपक्षीय पहलों में भारत की सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई), वैश्विक जैव-ईंधन गठबंधन और भारत-मध्य पूर्व- यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना में इसका अग्रणी होना देश के बढ़ते हितों और सहभागिताओं को दर्शाता है। इन समूहों के माध्यम से भारत ने सुधारित बहुपक्षवाद, शांति एवं सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण सामने रखा है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत, संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में एक अग्रगामी और रचनात्मक दृष्टिकोण वाला जुड़ाव रखता है। यह संयुक्त राष्ट्र में अपने हित के क्षेत्रों को सक्रिय तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसमें कई ऐतिहासिक पहलों को साकार करने में इसकी नेतृत्वकारी भूमिका भी शामिल है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप भागीदार देशों के साथ बेहतर सहयोग और घनिष्ठ जुड़ाव संभव हुआ है। भारत अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक विकास का भी एक दृढ़ समर्थक रहा है।

भारत एक प्रभावशाली वैश्विक पक्ष और जी-20 समूह में एक सुसंगत, संतुलित और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है, जिसने इसे पूर्व एवं पश्चिम के बीच और विकासशील एवं विकसित देशों के बीच एक प्रभावी सेतु और एकीकृत शक्ति के रूप में एक अद्वितीय स्थिति में ला दिया है। 2023 में जी-20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान, "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" विषय के तहत, "वसुधैव कुटुम्बकम" की हमारी सदियों पुरानी मान्यता को ध्यान में रखते हुए, भारत को विकासशील दुनिया की प्राथमिकताओं और चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर मिला और वह विश्व पटल पर विकासशील देशों के नेता के रूप में उभरा। भारतीय अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी-20 में शामिल किए जाने से वैश्विक दक्षिण की आवाज़ के रूप में भारत की भूमिका और भी बढ़ गई।

भारत संयुक्त राष्ट्र और इसकी सुरक्षा परिषद सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पुनर्गठन के लिए ब्रिक्स मंच का उपयोग करता है, जिसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। ब्रिक्स में साझा सूत्र बहु-ध्रुवीयता के प्रति प्रतिबद्धता है। ब्रिक्स की बैठकों और चर्चाओं का उद्देश्य साझा आधार खोजना और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने के लिए मिलकर काम करना है।

अपने सकारात्मक और रचनात्मक एजेंडे के साथ, क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में उभरा है। क्वाड की पहलों का उद्देश्य क्षेत्र की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करना, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के देशों को सार्वजनिक सामग्री की आपूर्ति करना है। भारत ने क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं में सहायता हेतु मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) संबंधी क्वाड साझेदारी स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। व्यावहारिक सहयोग के संबंध में क्वाड के सकारात्मक ध्यान केंद्रण को क्षेत्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

(ख) भारत की विदेश नीति जन-केंद्रित है, जो देश के लोगों की मांगों और आकांक्षाओं से निर्देशित होती है। भारत कई समूहों और अग्रणी पहलों में इस प्रकार से सम्मिलित हुआ है जिससे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत के जुड़ाव और हितों का संवर्धन हो। भारत, सभी के लिए, और विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि का पैरोकार है। भारत सदैव साथी विकासशील देशों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और वैश्विक दक्षिण के देशों के समग्र मानव-केंद्रित विकास के लिए रचनात्मक रूप से आगे आ रहा है।

विकासशील देशों के साथ भारत के जुड़ाव को गहन करने के लिए, भारत ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीन संस्करणों की मेजबानी की है। इन शिखर सम्मेलनों का उद्देश्य विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की

विकासात्मक प्राथमिकताओं और उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले समाधानों पर विचार-विमर्श करना था। शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 12-13 जनवरी, 2023 को 'यूनिटी ऑफ वॉयस, यूनिटी ऑफ पर्पस' के विषय के साथ आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 17 नवंबर 2023 को व्यापक विषय- 'एक साथ, सभी के विकास के लिए, सभी के विश्वास के साथ' के तहत आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण 17 अगस्त 2024 को "एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण" के व्यापक विषय के साथ आयोजित किया गया था। तीनों संस्करणों में 100 से अधिक देशों के नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इसके अलावा, वैश्विक दक्षिण के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं:

i. बड़े पैमाने पर अवसंरचना के विकास से लेकर स्वास्थ्य, आवास, पर्यावरण और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय से संबंधित परियोजनाएं शुरू करके कनेक्टिविटी और आर्थिक अंतर-संबंधों को बढ़ाना।

ii. साझेदार देशों की आर्थिक चुनौतियों को कम करने और संकट से उबरने में सहायता के लिए वित्तीय, बजटीय और मानवीय सहायता प्रदान करना।

iii. छात्रों और पेशेवरों को छात्रवृत्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके वैश्विक दक्षिण के देशों को क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास में योगदान देना।

विकासशील देशों के साथ भारत के संबंधों को गहन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने मार्च 2025 में मॉरीशस में महासागर सिद्धांत अर्थात "क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति" (सागर सिद्धांत का विस्तार) की रूपरेखा का उल्लेख किया।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और उभरते खतरों से निपटने के उद्देश्य से, भारत खुफिया सूचना-साझाकरण करारों सहित विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी और रक्षा करार/समझौता ज्ञापन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वैश्विक सहयोगियों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय नियमित रूप से संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक आयोजित करता है, जिसके दौरान खुफिया सूचना- साझाकरण करारों के प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाती है।

******